दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, बुधवार 05 मई 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 214

महत्वपूर्ण एवं खास

फुल लॉकडाउन ही कोरोना से बचने का एक मात्र रास्ताः राहुल

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना की रोकथाम के लिए पिछले साल लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन की आलोचना करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बार ऐसा पैंतरा बदला और यह कहने को मजबूर होते नजर आए कि कोरोना के प्रसार से बचने के लिए अब फुल लॉकडाउन ही एकमात्रा रास्ता बचा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत सरकार की निष्क्रियता की वजह से मासूम लोगों की जान जा रही है। राहुल गांधी ने कोरोना से निपटने के लिए खराब प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत सरकार समझ नहीं रही। इस स्थिति में कोरोना को फैलने से रोकने का एकमात्र रास्ता पूर्ण लॉकडाउन है। भारत सरकार की निष्क्रियता से कई मासूम लोग मर रहे हैं। बीते कई हफ्तों से राहुल गांधी कोरोना से निपटने को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। सोमवार को भी कर्नाटक के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 24 मरीजों के मारे जाने को राहुल गांधी ने हत्या करार दिया था। बता दें कि इस बीच मंगलवार को भारत में कोरोना वायरस के 3 लाख 57 हजार 229 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि, देश में कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो गया है। वहीं इस दौरान 3 हजार 449 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है।

लोकतंत्र में हिंसा अस्वीकार्य, स्थिति पर नियंत्रण करें ममता : कांग्रेस

नई दिल्ली (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा की निंदा करते हुए मंगलवार को कांग्रेस ने कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र में अस्वीकार्य हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्थिति पर नियंत्रण करना चाहिए। पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी जितिन प्रसाद ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने हमला किया है तथा महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। उन्होंने ट्वीट किया कि चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई हिंसा अस्वीकार्य है। महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के जोगों ने इस अराजकता के लिए वोट नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसी घटनाओं की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस तरह की हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया है।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन

नईदिल्ली (आरएनएस)। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जगमोहन दिल्ली और गोवा के उपराज्यपाल भी रहे। उन्हें एक बार राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। उन्होंने तीन बार लोकसभा की नई दिल्ली सीट का प्रतिनिधित्व किया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वे केन्द्रीय संचार, शहरी विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्री भी रहे। उन्हें वर्ष 1971 में पद्मश्री, 1977 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

देश में घटने लगी है कोरोना के नए मरीजों की संख्या

24 घंटे में मिले 3.57 लाख से ज्यादा नए मरीज

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर थमने का नाम नही ले रही, लेकिन अपने अनछुए रिकार्ड यानि चार लाख से ज्यादा दैनिक मामलों के चरम के बाद पिछले तीन दिन से इनमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3.57 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं, तो वहीं 3,449 लोगों की मौत हो गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 3,57,229 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2,02,82,833 हो गई है। इन 24 घंटों में 3,449 लोगों की कोरोना से हुई मृत्यु के कारण अब तक देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या

बढ़कर 2,22,408 हो गई है। भारत अब दुनिया का ऐसा दूसरा देश बन गया है, जहां कोरोना के कुल मरीजों की संख्या दो करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि महज 137 दिन में मामले एक करोड़ से दो करोड़ के पार पहुंच गए। इससे पहले संक्रमितों की संख्या एक लाख से एक करोड़ तक पहुंचने में 360 दिन लगे थे। मतलब चार माह में कोरोना के मामले दो गुने हो गए।

दस राज्यों में 73 फीसदी कोरोना केस- कोरोना वायरस की दूसरी लहर से लड़ रही भारत सरकार ने मंगलवार को ऐसे 10 राज्यों की सूचि जारी की है जिनमें कोरोना से देश की 73 प्रतिशत मौतें दर्ज की जा रही है. केंद्र सरकार के अनुसार केवल 10 राज्यों में नए कोविड -19 से होने वाली मृत्यु का 73.15 प्रतिशत हिस्सा है। पिछले 24 घंटों में 567 नई मौतों के साथ महाराष्ट्र देश का ऐसा सबसे खतरनाक राज्य बना हुआ है, जो महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां सबसे ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। इसके बाद दिल्ली दूसरे नंहर हैं जहां 448 नई मौतों दर्ज की गई हैं और 285 नई मौतों के साथ उत्तर प्रदेश, सूची में तीसरे नंबर पर स्थित हैं। भारत ने एक दिन की अवधि में 3,449 नई कोविड-19 मौतें दर्ज कीं हैं, जिसके बाद से देश में मृत्यु दर बढ़कर 222,408 हो गई है। इन दस राज्यो में पिछले 24 घंटों में इन तीन राज्यों के बाद छत्तीसगढ़ (266 मौतें), कर्नाटक (239 मौतें), पंजाब (155 मौत), राजस्थान (154 मौतें), हरियाणा (140 मौतें),गुजरात (140 मौतें) तथा झारखंड (129 मौत) शीर्ष पर हैं।केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा राष्ट्रीय मृत्यु दर पिछले कुछ दिनों से गिर रही है और वर्तमान में यह 1.10 प्रतिशत है। भारत ने मंगलवार को पिछले 24 घंटों में 357,229 नए कोविड -19 मामले दर्ज किए,जिसके बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार हो गई। इसी दौरान 3,449 नई मौतें भी दर्ज की गई, जिससे मरने वालों की संख्या 222,408 हो गई।

अब तक 1.66 करोड़ ने दी कोरोना को मात- स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 15 फरवरी के बाद से कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। राहत की बात ये है कि लगातार दूसरे दिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तीन लाख से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 3,20,289 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं, जबकि इससे एक दिन पहले 3,00,732 ठीक हुए थे। इस प्रकार देश में अब तक 1,66,13,292 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। जबकि देश में सक्रिय मामले बढ़कर 34,47,133 पहुंच गए हैं।

करीब 16 करोड़ का टीकाकरण- देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। अब तक 15,89,32,921 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इनमें से 17,34,714 लोगों का टीकाकरण मंगलवार को हुआ। 1 मई से कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। हालांकि अभी यह सभी राज्यों में शुरू नहीं हुआ है।

चार लाख से ज्यादा 18+ का वैक्सीकरण- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक देश में कुछ 15.89 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई है। इसमें से 17 लाख 8 हजार 390 खुराकें अकेले 3 मई को दी गई हैं। देश में एक मई से 18-44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हुआ है और अब तक इस उम्र के 4 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना टीका दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को झटका

» रेरा के बजाए बनाए गए कानून को बताया असंवैधानिक

नई दिल्ली (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने के लिए बनाए गए केंद्रीय कानून (रेरा), 2016 के स्थान पर 2017 में पारित किए गए वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्रीज रेगुलेशन एक्ट (हीरा), 2017 को निरस्त कर दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने पश्चिम बंगाल द्वारा बनाए गए हीरा (कानून) को शून्य और असंवैधानिक करार दिया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा है, यदि संसद ने किसी विषय पर कानून बनाया है, तो राज्य विधानमंडल के लिए समान कानून नहीं बना सकता है। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट, 2017 को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इसने एक समानांतर तंत्र और शासन का निर्माण किया, जो असंगत है। शीर्ष अदालत ने कहा, राज्य विधायिका ने समानांतर तंत्र लागू करके संसद की विधायी शक्ति पर अतिक्रमण किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार का कानून होम बायर्स के हितों की रक्षा करने में असफल रहा है। अदालत ने कहा कि राज्य कानून सीधे तौर पर केंद्रीय कानून के विरुद्ध है। लिहाजा इसे कायम नहीं रखा जा सकता। एक गैर सरकारी संगठन फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स ने राज्य कानून की वैधता को चुनौती देते हुए कहा था कि इससे घर खरीदारों को अपूरणीय क्षति हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने रेरा को लागू करने से इनकार कर दिया था और अपना कानून बनाया था।

पश्चिम बंगाल हिंसा पर एक्शन में आया चुनाव आयोग

» नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर को मिली सुरक्षा, बंगाल जाएगी महिला आयोग की टीम

नई दिल्ली (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से जारी हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः लिया है। यही नहीं महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के नेतृत्व में एक टीम बंगाल का दौरान करने वाली है। आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए टीम दौरा करेगी। महिला आयोग की

ओर से जारी बयान में कहा गया है, कि नंदीग्राम में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने जांच की मांग की है।

राज्य के डीजीपी को भेजे लेटर में आयोग की मुखिया रेखा शर्मा ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आरोपियों पर तत्काल एक्शन लिए जाने की मांग की है। महिला आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है, कि ट्विटर पर आयोग ने ऐसी कई पोस्ट देखी हैं, जिनमें नंदीग्राम में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जा रही है। ऐसी तस्वीरों से महिला आयोग आहत हुआ है। इससे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ है। आयोग की मुखिया रेखा शर्मा ने राज्य के डीजीपी को खत लिखकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आरोपियों पर तत्काल एक्शन लेने की मांग की है। इन घटनाओं की समयबद्ध जांच कराने की भी मांग की है। इसके अलावा मामले की जांच के लिए अध्यक्षा रेखा शर्मा की लीडरशिप में एक टीम भी बंगाल का दौरा करने वाली है।

यही नहीं नंदीग्राम में रिटर्निंग ऑफिसर रहे अधिकारी को राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा प्रदान की गई है। सरकार ने चुनाव आयोग को यह जानकारी दी है। आयोग ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार से कहा था कि वह नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर को पर्याप्त सुरक्षा कवर मुहैया कराए। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंच गए हैं। राज्य में पहुंचते ही उन्होंने हिंसा का शिकार हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाकर मुलाकात की है।

प्रधान ने बायोडीजल की पहली आपूर्ति को हरी झंडी दिखाई

नईदिल्ली (आरएनएस)। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इंडियन ऑयल के टिकरीकलां टर्मिलन, दिल्ली से आईओआई योजना के तहत यूसीओ (प्रयुक्त खाद्य तेल) आधारित बायोडीजल मिश्रित डीजल की पहली आपूर्ति को हरी झंडी दिखाई।इस अवसर पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर और इंडियन ऑयल के अध्यक्ष एस. एम. वैद्य भी उपस्थित थे।

यूसीओ को बायोडीजल में परिवर्तित करने और उद्यमिता के अवसरों को विकसित करने को लेकर एक इकोसिस्टम बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथपेट्रोलियम एवंप्राकृतिक

गैस मंत्रालय ने 10 अगस्त, 2019 को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रयुक्त खाद्य तेल से उत्पादित बायोडीजल की खरीद के लिए अपनी दिलचस्पी व्यक्त की थी। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा समय-समय पर इस तरहदिलचस्पी के भावव्यक्त किए जाते हैं।पहले चरण में 200 जगहों के लिए 10 अगस्त, 2019 से 9 नवंबर, 2020 के बीच11 ईओआई जारी किए गए थे। पूरे देश में 300 स्थानों के लिए ईओआई का प्रकाशन 31 दिसंबर, 2021 तक यानी एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है।

इस पहल के तहत, ओएमसी पांच साल के लिए समय-समय पर वृद्धिशील मूल्य की गारंटी देते हैं और संभावित उद्यमियों को दस साल के लिए ऑफ-टेक गारंटी देती हैं। अब तक, इंडियन ऑयल ने 22.95 करोड़ लीटर (557.57 टीपीडी)की कुल क्षमता वाले बायोडीजल संयंत्रों के लिए 23 एलओआई भी जारी की है। इस पहल के तहत, इंडियन ऑयल को दिल्ली स्थित अपने टिकरीकलां टर्मिनल 31 मार्च, 2021 तक 51 किलोलीटर (केएल)यूसीओ-बायोडीजल का प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान नेमहामारी की कठिन चुनौतियों के बावजूद ईंधन लाइनों को चालू रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तेल उद्योग की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने इस संकट में राष्ट्र को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए समर्थन देकर व्यावहारिक व्यापार अनिवार्यता से आगे जाने को लेकर भी ओएमसी की सराहना की।प्रधान ने विभिन्न पहलों के माध्यम से देश में तरल ऑक्सीजन लॉजिस्टिक्सको सुचारू बनाने के लिए इंडियन ऑयल की नेतृत्वकारी भूमिका की सराहना की। इंडियन ऑयल के टिकरीकलां टर्मिनल से यूको आधारित बायोडीजल की पहली आपूर्ति के बारे में प्रधान ने कहा, यहभारत के जैव ईंधन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है और इसका पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ेगा। यह पहल स्वदेशी बायोडीजल आपूर्ति को बढ़ाने, आयात निर्भरता कम करने औरग्रामीण रोजगार को पैदा करकेराष्ट्र को पर्याप्त आर्थिक लाभ प्रदान करेगी।

सरकार ने कोविड राहत सामग्री के प्रभावी आवंटन और वितरण में समय नष्ट नहीं किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। इंडिया टुडे ने अपनी खबर में आरोप लगाया है कि 25 अप्रैल को कोविड-19 सहायता की पहली खेप भारत आई थी। इसके बाद केंद्र ने इन जीवन-रक्षक चिकित्सा आपूर्तिओं को वितरित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने में सात दिन का समय लिया।

यह खबर तथ्यात्मक जानकारी को गलत तरीके से सामने रखती है और पूरी तरह भ्रामक है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2 मई, 2021 को आवंटन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई थी, लेकिन केंद्र और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को रसीद, आवंटन और वितरण का काम तत्काल शुरू कर दिया गया था, जैसा कि वैश्विक समुदाय ने इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार के प्रयासों के लिए सहायता करना शुरू कर दिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय में 26 अप्रैल, 2021 को अतिरिक्त सचिव (स्वास्थ्य) के तहत समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया गया था और इसने तुरंत काम करना शुरू कर दिया था। विभिन्न हितधारकों के बीच शीघ्र और प्रभावी समन्वय के लिए अंतर-मंत्रिस्तरीय सेल में शिक्षा मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर एक संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय से दो अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी, साथ अन्य प्रतिनिधि शामिल हैं।

तीन राज्यों में 9 फीसदी महिलाएं बनी विधायक

नई दिल्ली (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों की नवनिर्वाचित विधानसभा में पिछली बार की तुलना में इस बार कम राजनीतिक दल होंगे। आधिकारिक डाटा के मुताबिक 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 8 पार्टी के विधायक थे, वहीं इस बार केवल 3 दलों के ही प्रतिनिधि रहेंगे। वहीं तमिलनाडु और केरल विधानसभा की बात करें तो, यहां परिस्थिति पश्चिम बंगाल से बिल्कुल विपरीत है। तमिलनाडु की 234 सीटों वाली विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले दलों की संख्या दोगुनी हो गई है। यानी 2016 में विधायक 4 दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहीं इस बार 8 दलों के विधायक चुनकर आए हैं। इसी प्रकार 140 सीटों वाली नवनिर्वाचित केरल विधानसभा की तो यहां 16 दलों के प्रतिनिधि हैं। लेकिन इन प्रतिनिधियों की कुल संख्या में केवल 9 फीसदी ही महिला विधायक हैं। जानिए पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में कितनी महिला विधायक चुनी गई हैं।. पश्चिम बंगाल से 14, केरल से 8 और तमिलनाडु से 5 फीसदी महिलाएं ही विधायक बनी हैं। यानी पुरुष के मुकाबले केवल 9.4 महिलाएं ही चुनाव जीती हैं। जिसमें से 38.33 बारहवीं, 40.7 स्नातक और 21 फीसदी स्नातकोत्तर पास हैं। अगर बात करें उम्र की तो 25 से 40 उम्र की 9.6, 41 से 55 उम्र की 41.3, 56 से 70 उम्र की 40.66 और 70 से अधिक उम्र की 8.33 फीसदी महिलाएं यह चुनाव जीती हैं।

668 विधायकों में से केवल 63 महिलाएं- इन तीन राज्यों की नवनिर्वाचित विधानसभा में से केवल केरल में महिला विधायक की संख्या में बढ़ौतरी देखने को मिली है। 2016 में 8 महिला विधायक चुनी गई थी, वहीं 2021 में 11। पश्चिम बंगाल की बात करें, तो यहां महिलाओं ने 40 सीटों पर अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, जबकि 2016 में यह संख्या 41 थी।

आयुष-64 दवा कोविड 19 के हल्के और कम गंभीर मामलों के उपचार में कारगर

» आयुष मंत्रालय ने पूछे जाने वाले सवालों के दिये जवाब

नईदिल्ली (आरएनएस)। कई जड़ी-बूटियों को मिलाकर बनाई गई आयुष-64 दवा को इस महामारी के समय में विशेषज्ञों ने उम्मीद की किरण बताया है। इस दवा को मूलरूप से मलेरिया के उपचार के लिये 1980 में विकसित किया गया था। अब उसे कोविड 19 के उपचार के लिये भी उपयुक्त पाया गया है। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) आयुष मंत्रालय के अधीन आयुर्वेद में शोध करने वाला एक अग्रणी

संस्थान है। उसने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के सहयोग से हाल में इस दवा का विस्तृत और गहन परीक्षण किया है। इसमें देश के अन्य अनुसंधान संगठनों और मेडिकल कॉलेजों का भी सहयोग लिया गया। देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने आयुष 64 का जो क्लीनिकल परीक्षण किया, उसमें पता लगा कि इस दवा में वाइरस के खिलाफ लड़ने, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और बुखार उतारने के गुण हैं। इसे लक्षण-रहित, हल्के और कम गंभीर कोविड 19 संक्रमण के उपचार के लिये भी कारगर पाया गया। परिणामस्वरूप, इस दवा को कोविड 19 के उपचार के लिये उपयुक्त मान लिया गया है।

आयुष मंत्रालय ने क्लीनिकल परीक्षण के नतीजों की घोषणा 29 अप्रैल, 2021 को एक प्रेस-कांफ्रेंस में की थी। उसके बाद आम जनता और चिकित्सा कार्य से जुड़े लोगों में आयुष-64 के प्रति दिलचस्पी बढ़ी है। इस विषय में कई जिज्ञासायें मिली हैं। मंत्रालय ने अब प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों के रूप में जवाब जारी किये हैं, जिन्हें नीचे दिया जा रहा है:

आयुष क्या है?

आयुष एक आयुर्वेदिक नुस्खा है, जिसे केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है, जो आयुष मंत्रालय के अधीन आयुर्वेद अनुसंधान की प्रमुख संस्था है। मूल रूप से इसे 1980 में मलेरिया के उपचार के लिये विकसित किया गया था। अब इस दवा को कोविड 19 के उपचार के लिये भी उपयोगी माना गया है, क्योंकि इसमें वाइरस से लड़ने, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और बुखार उतारने के गुण हैं। आयुष 64 के वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया है कि इसके 36 घटकों में से 35 घटक ऐसे हैं, जो कोविड 19 के वाइरस के खिलाफ एक-जुट होकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। इस नुस्खे में ऐसे भी घटक मौजूद हैं, जो फ्लू जैसी बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। देश भर में 64 क्लीनिकल परीक्षण हुये हैं। इन परीक्षणों से जो सबूत मिले हैं, उनसे साबित होता है कि लक्षण-रहित, हल्के और कम गंभीर कोविड 19 के इलाज में यह दवा बहुत कारगर है और इससे मरीज जल्द ठीक हो सकता है।